भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4784
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तिब्बत में बांध का निर्माण

4784. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा तिब्बत में यरलंग सांगपो (या जांगबो) नदी पर विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के निर्माण को चीन द्वारा स्वीकृति दिए जाने के संबंध में अपनी चिंताओं को दर्ज कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार की इस गंभीर मुद्दे पर चीनी सरकार के साथ सुसंगत माध्यम से संवाद की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ऐसी परियोजना के मूर्त रूप लेने की स्थिति में पहले से ही शमन और अनुकूलन उपाय करने की योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) भारत सरकार ने तिब्बत में यरलंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र का ऊपरी हिस्सा) नदी के निचले इलाकों में एक विशाल बांध परियोजना को मंजूरी देने की चीन की घोषणा पर ध्यान दिया है। सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक नज़र रखती है, जिसमें चीन द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं को विकसित करने की योजना भी शामिल है, और अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है, जिसमें निचले इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय शामिल हैं।

चीन के साथ सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वर्ष 2006 में स्थापित संस्थागत 'विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र' के तहत तथा राजनयिक माध्यमों से चर्चा की जाती है। सरकार ने सीमा पार नदियों के जल पर पर्याप्त स्थापित उपयोगकर्ता अधिकारों वाले एक निचले तटवर्ती देश के रूप में लगातार चीनी प्राधिकारियों को अपने विचार और चिंताओं से अवगत कराया है, तथा उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उच्च तटवर्ती क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि से निचले तटवर्ती राष्ट्रों के हितों को क्षति न पहुंचे। चीन द्वारा हाल ही में मेगा बांध परियोजना की घोषणा के बाद, सरकार ने 30 दिसंबर 2024 को चीनी पक्ष को अपनी चिंताओं से अवगत कराया, जिसमें पारदर्शिता की आवश्यकता और निचले तटवर्ती देशों के साथ परामर्श शामिल है।

यह मुद्दा भारत और चीन के मध्य विदेश सचिव-उप विदेश मंत्री तंत्र की बैठक के लिए विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री की बीजिंग यात्रा के दौरान भी उठाया गया था। यात्रा के दौरान, भारत और चीन ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा के प्रावधान को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदियों से संबंधित अन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की शीघ्र बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए सीमा पार नदियों के मुद्दे पर चीन के साथ वार्ता जारी रखने की इच्छा रखती है।

*****